



Felt.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असौधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 1 फरवरी, 2006 / 12 माघ, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 31 जनवरी, 2006

संख्या पी० बी० डब्ल्यू (बी० एण्ड आर)बी०(४)२-३/२००५.—मैसर्स के० के० रोपवेज लिमिटेड, चम्बाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने जाबली से कसौली, द्वितीय चरण नन्दोह से दोची (लोअर माल कसौली के समीप), जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में यात्री आकाशी रज्जू मार्ग का विनिर्माण करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था;

और राज्य सरकार ने, हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जू मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का 7) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी हितबद्ध व्यक्तियों से तारीख 24-12-2005 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित इस सरकार की समसंख्यक सूचना तारीख 20 दिसम्बर, 2005 द्वारा आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित किए थे;

और राज्य सरकार द्वारा उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्ज के 0 के 0 रोपवेज लिमिटेड, चम्बाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश (सम्प्रवर्तक) को, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्वधीन, जाबली से कसौली, द्वितीय चरण नन्दोह से दोच्ची (लोअर माल कसौली के समीप), जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में आकाशी रज्जू मार्ग का विनिर्माण करने की अनुज्ञा देते हैं और प्राधिकृत करते हैं:—

- (i) यह कि सम्प्रवर्तक, हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जू मार्ग अधिनियम, 1968 की धारा 7 के अधीन अन्तिम आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आदेश" कहा गया है) के प्रकाशन के छह मास के भीतर पूंजी जुटाएगा;
- (ii) यह कि रज्जू मार्ग के प्रतिष्ठापन से सम्बन्धित विनिर्माण के सिविल कार्य, संयन्त्र और तंत्र आदेश के प्रकाशन के तुरन्त बाद शुरू किए जाएंगे;
- (iii) यह कि आकाशी रज्जू मार्ग का विनिर्माण, आदेश के प्रकाशन के पश्चात्, तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा;
- (iv) यह कि सम्प्रवर्तक, ऐसी रियायतों के लिए पात्र होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुज्ञात की जाएं;
- (v) यह कि संपरीक्षा तथा लेखों के बारे में नियम, कर और कम्पनी अधिनियमों/नियमों के अनुसार होंगे;
- (vi) यह कि सम्प्रवर्तक, राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मानकों, परिमाणों और विनिर्देशों के अनुरूप आकाशी रज्जू मार्ग का विनिर्माण करेगा। संरचनात्मक डिज़ाईन, सामग्री की गुणवत्ता, सुरक्षा कारक तथा भार की संगणना का ढंग उनके अनुरूप होगा जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकथित किए गए हैं और अर्हित संरचना अभियंता द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया जाएगा। परन्तु, यदि स्थल की परिस्थिति के कारण परिमाण और विनिर्देशों में कोई विचलन हो, जिसके अन्तर्गत टावर की ऊंचाई में 15.00 मीटर से अधिक परिवर्तन भी है, तो सम्प्रवर्तक

निरीक्षक, रज्जू मार्ग विशेषज्ञ समिति की पूर्वानुमति अभिप्राप्त करेगा। संरचनात्मक डिजाइन और सामग्री की गुणवत्ता, सुरक्षा कारक मोनोकेबल फिक्स ग्रिप पद्धति को यथा लागू हिमाचल प्रदेश रज्जू मार्ग अधिनियम, 1968 तथा भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे;

(vii) यह कि सम्प्रवर्तक, सड़क तथा अन्य सार्वजनिक संचार साधनों के मार्गों के ऊपर से आकाशी रज्जू मार्ग के विनिर्माण के विषय में उन नियमों का पालन करेगा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू हैं। रज्जुमार्ग रेलगाड़ी की पटरी को क्रॉस ओवर नहीं करेगा;

(viii) यह कि सम्प्रवर्तक, उपर्युक्त आकाशी रज्जू मार्ग या इसके किसी भाग को, राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, हस्तांतरित नहीं करेगा या पट्टे अथवा उपपट्टे (सबलेट) पर नहीं देगा। कोई भी प्राधिकरण, -- पारस्परिक स्वीकार्य लागत प्रतिकर संदत्त करने के पश्चात् फरियोजना का क्रय कर सकेगा। सम्प्रवर्तक यदि ऐसा समझते हैं कि वे किन्हीं भी कारणों से रज्जू मार्ग को चलाने में असमर्थ हैं, तो वे पारस्परिक स्वीकार्य प्रतिकरों के लिए अपने अधिकार सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकेंगे। रज्जुमार्ग को ग्रहण करना, सम्प्रवर्तकों से प्रतिग्राह्य प्रतिकर पर बातचीत करने के पश्चात्, सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा;

(ix) यह कि सम्प्रवर्तक, आकाशी रज्जू मार्ग के संचालन हेतु मुख्य रूप में विद्युत् शक्ति का प्रयोग इस शर्त के अध्यधीन करेगा कि विद्युत् फेल होने की दशा में वह आकाशी रज्जू मार्ग के संचालन के लिए उसकी जगह डीजल जैनेरेटिंग सैट हमेशा तैयार रखने का प्रबन्ध करेगा। विद्युत् शक्ति का प्रदाय हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड करेगा;

(x) यह कि सम्प्रवर्तक, विश्वस्त यंत्र, उचित संकेत व्यवस्था, उचित डिजाइन फिक्सचर और संरचनात्मक रस्सियां, मशीनरी, गियर तथा अन्य साधित्रों की व्यवस्था करेगा। सम्प्रवर्तक प्रतिदिन सुनिश्चित करेगा कि मशीनरी, साधित्र इत्यादि ठीक हैं और इनमें नियमित रूप से उचित ग्रीस और तेल लगाया गया है;

(xi) यह कि आकाशी रज्जू मार्ग रेल लाईन के ऊपर से गुजरने की दशा में सम्प्रवर्तक रेल प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करेगा;

(xii) यह कि सम्प्रवर्तक, आयुद्ध अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत आने वाले आयुद्ध और गोला बारूद के सिवाय, यात्रियों को उनके सामान सहित जैसे कि ब्रीफकेस/ अटैची/ सूटकेस/ हैंडबैग इत्यादि, आकाशी रज्जू मार्ग से ले जाएगा;

- (xiii) यह कि रज्जु के विभिन्न भागों के अधीन बनाई रखी जाने वाली न्यूनतम ऊंचाई (हैडवे) सुसंगत भारतीय मानकों के अनुरूप होगी;
- (xiv) यह कि यदि सुसंगत अधिनियम/नियमों के अधीन अपेक्षित हो, संरक्षण पुल विनिर्मित किया जाएगा तथा बनाए रखा जाएगा;
- (xv) यह कि पर्यटन मूलक परियोजना होने के कारण यातायात मूलतः पर्यटकों का होगा। तथापि, टिकटों के लिए संदाय करने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति रज्जुमार्ग पर यात्रा कर सकेगा;
- (xvi) यह कि सम्प्रवर्तक, इस नोटिस से संलग्न उपाबन्ध-1 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक दरें प्रभारित नहीं करेगा;
- (xvii) यह कि सम्प्रवर्तक, आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक प्रत्याभूति के रूप में 3,00,000/- रूपए (तीन लाख रूपए) की प्रतिभूति, सचिव (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम पर देगा। किसी शर्त के किसी भंग की दशा में, राज्य सरकार उक्त प्रतिभूति को समपहृत करने के लिए स्वतंत्र होगी। प्रतिभूति के समपहरण का आदेश देने से पूर्व, सचिव (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार, सम्प्रवर्तक को ऐसे भंग का निश्चित रूप से 15 दिन के भीतर सुधार करने के लिए कारण बताओ नोटिस देगा और यदि सम्प्रवर्तक सुधार करने में असफल रहता है तथा भंग के लिए समुचित स्पष्टीकरण देता है, तो राज्य सरकार, राज्य सरकार के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा अन्तिम आदेश, जैसा यह उचित समझे, कर सकेगी;
- (xviii) यह कि सम्प्रवर्तक, ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे प्ररूप में जैसे राज्य सरकार समय-समय पर विहित करे, पूंजी और राजस्व-व्यय, प्राप्तियों और यातायात की विवरणियां राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा;
- (xix) यह कि यदि सम्प्रवर्तक, उपरोक्त विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी का भंग करता है या पूर्वोक्त अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है अथवा उपर्युक्त रज्जु मार्ग के चलाने/संचालन करने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार आकाशी रज्जु मार्ग को सभी विल्लंगमों से मुक्त या अवक्षय (गिरावट) बही मूल्य पर ग्रहण कर/ले सकेगी। यदि राज्य सरकार उक्त रज्जु मार्ग का ग्रहण करने का आशय नहीं रखती है तो स्थानीय प्राधिकरण उसकी अवक्षय बही मूल्य पर या सम्प्रवर्तक और स्थानीय प्राधिकरण के बीच परस्पर करार पाए गए मूल्य पर इसका कय कर सकेगा;

- (xx) यह कि सम्प्रवर्तक, निरीक्षक/विशेषज्ञ समिति या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सभी युक्तियुक्त समयों पर आकाशी रज्जु मार्ग का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा;
- (xxi) यह कि पूर्वोक्त अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन, आदेश की शर्तों का भंग माना जाएगा;
- (xxii) यह कि राज्य सरकार द्वारा किसी बचाव क्रिया के दौरान उपगत व्यय, सम्प्रवर्तक द्वारा राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा और सम्प्रवर्तक इसे पूर्णतया अथवा इसके भाग को संदत्त करने में असफल रहता है तो वह भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगा; और
- (xxiii) यह कि यदि राज्य सरकार और सम्प्रवर्तक के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह एक मात्र माध्यस्थम् अर्थात् मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, को निदेशित किया जाएगा, जिनका विनिश्चय अन्तिम और दोनों पक्षों पर बाध्य होगा। माध्यस्थम् के समक्ष कार्यवाहियां, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के द्वारा नियमित की जाएंगी।

आदेश द्वारा,

सुभाष सी० नेगी,  
प्रधान सचिव।

## उपाबन्ध—1

ज़ाबली से कसौली तक द्वितीय चरण, नन्दोह से दोची (लोअर माल कसौली के समीप), जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में लगाए जाने वाले आकाशी रज्जु मार्ग द्वारा यात्रियों को वहन करने के लिए सम्प्रवर्तक द्वारा प्रभारित की जा सकने वाली अधिकतम दरों की अनुसूची

क्रम संख्या    व्यक्तियों का विवरण    दोनों तरफ की यात्रा के लिए अधिकतम दरें (रुपए में)

1	3 वर्ष से कम आयु के बच्चे	छूट
2	3 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे	100 -
3	12 वर्ष से अधिक आयु के अन्य व्यक्ति	200

टिप्पणी 1.—सम्प्रवर्तक, यात्रियों से हल्का सामान जैसे ब्रीफकेस, छोटे सूटकेस और हाथ के बैगों आदि के लिए कोई प्रभार नहीं लेगा।

टिप्पणी 2.—सम्प्रवर्तक, यात्रियों के भारी सामान के भण्डारण हेतु सामान गृह का प्रबन्ध करेगा और उस सम्बन्ध में उन्हें समुचित रसीद जारी करेगा।

टिप्पणी 3.—उपरोक्त किराए की दरें यात्रियों से दोनों तरफ की यात्रा के लिए प्रभारित की जाएंगी।

टिप्पणी 4.—दरें आगत लागत (इनपुट कॉस्ट) के बढ़ने/घटने की दृष्टि से पुनरीक्षित की जा सकेंगी।

[Authoritative English text of this Government Notification No PBW(B&R)(B)8(2)3/2005 dated 31-1-2006 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]

## PUBLIC WORKS DEPARTMENT

### ORDER

*Shimla-2, the 31st January, 2006*

**No. PBW(B&R)(B)8(2)3/2005.**—Whereas M/s K. K. Ropeways Ltd., Chambaghat, District Solan (H. P.) had applied for permission to construct passenger aerial ropeway from Jabli to Kasauli Phase-II from Nandoh to Dochi (near Lower Mall, Kasauli), District Solan (H. P.);

And whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969), the State Government had invited the objection(s)/suggestion (s) *vide* this Government Notice of even number dated 20<sup>th</sup> December, 2005, published in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extra-ordinary) dated 24<sup>th</sup> December, 2005 from all interested persons;

And whereas no suggestion(s)/objection(s) have been received by the State Government within the stipulated period.

Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Act *ibid*, is pleased to grant permission and authorise the construction of an aerial ropeway from Jabli to Kasauli Phase-II from Nandoh to Dochi (near Lower Mall, Kasauli), District Solan

(H. P.) by M/s K. K. Ropeways Ltd., Chambaghat, District Solan (H. P.) (Promoter) subject to the following restrictions and conditions:—

- (i) that the promoter shall raise capital within 6 months of the publication of the final order under section 7 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 ( hereinafter called “the order”);
- (ii) that the construction of civil works, plant and machinery connected with the ropeway installation shall start immediately after publication of the order ;
- (iii) that the construction of the aerial ropeway shall be completed within a period of 3 years after the publication of the order ;
- (iv) that the promoter shall be eligible for such concessions as may be allowed by the State Government from time to time ;
- (v) that the rules regarding audit and accounts shall be as per Taxation and Company Acts/Rules ;
- (vi) that the promoter shall construct the aerial ropeway conforming to the standards, dimensions and specifications as approved by the State Government. The structural designs, quality of material, factor of safety, method of computing stresses shall be in conformity with those as laid down by the Bureau of Indian Standards and shall be duly certified by a qualified structural engineer. Provided that if there is any deviation in the dimension and specification on account of site condition including change in the height of the tower beyond 15.00 metres, the promoter shall obtain the prior permission of the Inspector, Ropeway Expert Committee. The specifications relating to structural designs and quality of material, factors of safety shall conform to the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 and Indian Standards as applicable to the Monocable Fixed Grip System ;
- (vii) that the promoter shall follow the rules which are applicable in the State of Himachal Pradesh regarding construction of aerial ropeway over the roads and other public ways of communications. The ropeway shall not cross over Railway line ;



- (viii) that the promoter shall not sell, transfer, lease or sublet the aforesaid aerial ropeway or part thereof to any other person without the prior permission of the State Government. Any authority can purchase the project after paying the mutually agreed cost compensation. In case the promoter feels that they are incapable of running the ropeway for any reasons whatsoever, they may transfer their rights to Government, Local Authority or any other person, for mutually agreed compensations. The taking over of the ropeway has to be decided by the Government after negotiating the compensation acceptable to the promoters ;
- (ix) that the promoter shall use electricity power as the main mode for operating the aerial ropeway subject to the condition that in case of the failure of electricity he shall always keep standby arrangement of Diesel Generating Set for the operation of the aerial ropeway. The electric power shall be supplied by the Himachal Pradesh State Electricity Board ;
- (x) that the promoter shall provide reliable devices, provisions for the signaling, suitable designed fixtures and structural ropes, machinery, gear and other appliances. The promoter shall daily ensure that the machinery appliances etc. are in order and properly greased and oiled regularly ;
- (xi) that the promoter shall obtain the permission from the Railway Authorities in case the aerial ropeway passes over the railway line ;
- (xii) that the promoter shall carry passengers with their luggages such as briefcases/attachee/suitcase/handbag etc. on the aerial ropeway, except arms and ammunitions as covered under the Arms Act, 1959 ;
- (xiii) The minimum headway to be maintained under different parts of the rope shall be as per the relevant Indian Standards ;
- (xiv) Protection Bridge will be constructed and maintained, if required under the relevant Act/Rules ;
- (xv) Being a tourism oriented project, the traffic will consist of mainly tourists. However anybody can travel on Ropeway after paying for the tickets ;

- (xvi) that the promoter shall not charge the rates higher than the rates approved by the State Government as per annexure-I annexed to this notice ;
- (xvii) that the promoter shall submit a security of Rs. 3.00 lacs (Rupee three lacs) in the shape of bank guarantee, from any nationalized bank in the name of Secretary (PWD) to the Government of Himachal Pradesh for due compliance of the conditions specified in the order. In the case of any breach of any condition, the State Government shall be at a liberty to forfeit the said security. Before ordering the forfeiture of the security, Secretary (PWD) to the Government of Himachal Pradesh shall give show cause notice to the promoter to rectify the breach within 15 days positively and if the promoter fails to rectify and give suitable explanation for breach, the State Government may make order as it may think fit without prejudice to the other rights of the State Government ;
- (xviii) that the promoter shall submit to the State Government such returns of the Capital and Revenue Expenditure, receipts and tariff at such interval and in such form as may be prescribed by the State Government from time to time ;
- (xix) that in case the promoter commits any breach of any of the conditions specified above or acts in contravention of provision of the Act *ibid* and rules framed thereunder or fails to operate/run the aforesaid ropeway, the State Government may take-over/resume the aerial ropeway free from all encumbrances or on depreciated book values of the aerial ropeway. In case the State Government does not intend to take over the said ropeway, the local authority may purchase the same on the depreciated book value or as may be mutually agreed between the local authority and promoter ;
- (xx) that the promoter shall allow the Inspector/Expert Committee or their authorized representative to inspect the aerial ropeway at all reasonable times ;

- (xxi) that the contravention of the any of the provisions of the Act *ibid* or rules framed thereunder shall be termed as a breach of the condition of the order ;
- (xxii) that the expenditure incurred by the State Government during any rescue operation, shall have to be paid by the promoter to the State Government and in case the promoter fails to pay the whole or part of it, the same shall be recoverable as an arrears of the land revenue; and
- (xxiii) that if any dispute arises between the State Government and the promoter, the same shall be referred to the sole Arbitrator *i.e.* the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh whose decision thereupon shall be final and binding on both the parties. The proceedings before the Arbitrator shall be regulated by the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

By order,

SUBHASH C. NEGI,  
Principal Secretary.

## ANNEXURE-I

**Schedule of Maximum Rates which can be charged by the promoter for carrying passengers through the aerial ropeway to be installed between Jabli to Kasauli Phase-II from Nandoh to Dochi (near Lower Mall, Kasauli), District Solan (H. P.)**

<i>Sl. No.</i>	<i>Description</i>	<i>Maximum rates in Rupees for both ways Journey of persons</i>
1.	Children below the age of 3 years	Exempted
2.	Children from 3 to 12 years of age	100
3.	Other persons over the age of 12 years	200

Note 1.—The promoter shall not charge anything for the small luggage like briefcase, small suitcase and handbags etc. from the passengers.

Note 2.—The promoter shall provide a luggage room for storing the bigger luggage of the passengers and shall issue proper receipt.

Note 3.—The above rates of fare shall be charged from passengers for both way journey.

Note 4.—The rates may be revised in view of the increase/decrease of input cost.